दलितों के साथ रहने वाले ग़ैर-दलित छात्र जब वापस घर लौटते हैं तो उनके मां-बाप शुद्धिकरण के लिए क्या तरीके अपनाएंगे?

ढाई साल पहले गुजरात पुलिस से रिटायर्ड दलित आईपीएस अफ़सर राजन प्रियदर्शी ने 'दलितों पर अत्याचार' विषय पर पीएचडी के दौरान ग़ैर-दलित छात्रों को प्रश्नपत्र में यही सवाल पूछा।

बच्चों ने बताया कि मां-बाप उन्हें गाय छूने को कहेंगे जिससे वो पवित्र हो जाएंगे। गंगाजल छिड़कने पर शुद्धता आएगी। मुसलमान को छूने से भी अशुद्धियाँ दूर होंगी। उनसे सूरज की ओर लगातार देखने को कहा जाएगा जिससे शरीर शुद्ध होगा।

गैर-दलितों की सोच

राजन प्रियदर्शी कहते हैं, "इस प्रश्नपत्र में जवाब से पता चला कि ग़ैर-दलित, दलितों के साथ खाने को तो दूर उन्हें पड़ोसी बनाने को भी तैयार नहीं थे।"

आईजी के पोस्ट तक पहुंचने वाले प्रियदर्शी अपने गांव में उच्च जातियों के दबाव के कारण अपना घर तक नहीं बना पाए। मज़बूरन वो अहमदबाद के एक दलित-बहुल इलाक़े में रह रहे हैं।

वो कहते हैं, "गुजरात में कोई दलित अपनी मनपसंद जगह में नहीं रह सकता।"

गुजरात में दलितों की संख्या केवल सात फ़ीसद है और जाति आधार पर विभाजित गुजराती समाज में दलित सबसे नीचे हैं।

गुजरात के 1589 गावों में रिसर्च

कुछ समय पहले रॉबर्ट एफ़ केनेडी फ़ॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ने स्थानीय नवसर्जन ट्रस्ट के साथ दलितों के हालात पर गुजरात के 1589 गांवों का अध्ययन किया। इसमें पता चला कि दलितों के साथ 98 तरह से छुआछूत किया जाता है।

पाया गया कि 98.1 फ़ीसद गांवों में दलित ग़ैर-दलित के यहां मकान किराए पर नहीं ले सकता। 97.6 फ़ीसद गांवों में दलित ग़ैर-दलित के बर्तन को नहीं छू सकता। 67 फ़ीसद गांवों में दलित पंचायत सदस्यों के लिए अलग 'दलित कप' हैं।

56 फ़ीसद गांवों के चाय ढाबों में दलितों और ग़ैर-दलितों के अलग-अलग कप हैं। और हां दलित की जिम्मेदारी है कि वो अपने कप को धोकर ग़ैर-दलितों के कप से दूर रखें। 53 फ़ीसद गांवों में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि वो अपना पानी घर से लाएं।

नवसर्जन की मंजुला प्रदीप बताती हैं, "पहले बसों में दलितों को ग़ैर दलित को सीटें देनी पड़ती थीं। वो कुएं से ख़ुद पानी नहीं भर सकते थे। उन्हें ऊपर से पानी दिया जाता था। दलितों के लिए अलग प्लेट हैं जिसे रक़ाबी कहते हैं। शोध में पाया गया कि 77 फ़ीसद गांवों में मैला ढोने की व्यवस्था है।"

दलितों को देते हैं मृतक की चारपाई

वो बताती हैं ग़ैर दलित की मौत पर कफ़न वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति को दिया जाता है। जिस चारपाई में व्यक्ति की मौत हुई है, वो दलित को दे दी जाती है। दलित बच्चों से ही टायलेट की सफ़ाई करवाई जाती है।

इन सबसे परेशान होकर दलित शहर जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें मकान नहीं दिया जाता। अहमदाबाद में दलितों के अलग मोहल्ले हैं, जैसे बापूनगर, अमराईवाड़ी, वेजलनगर। अमीर दलित अपनी सोसाइटी में रहते हैं।

गांवों के मुख्य गरबे में दलित शामिल नहीं हो सकते। उनके श्मशान तक अलग हैं। कारण -दलित के जलने से निकलने वाले धुएं से पवित्रता नष्ट होगी। श्मशान न होने के कारण दलितों को अपने मृतकों को दफ़नाना भी पड़ता है।

दलित श्मशान

गांधीनगर से 50 किलोमीटर दूर बाउली गांव में ऐसा ही एक दलित श्मशान है। ऊपर टीन की चादर। चार लोहे के लंबे खंबे। कांक्रीट की ज़मीन। ज़मीन पर राख का निशान। जैसे थोड़े वक्त पहले ही कोई मानव शरीर राख हुआ हो। चारों ओर से छोटी दीवार का घेरा। गांव के एक कोने में दलितों के मकान है। अमीर पटेल इलाकों से उलट यहां न सड़क है, न शौचालय। चारों ओर गड्ढे, गड्ढों में मैला पानी, जो पानी के पाइप के पानी से मिलकर लोगों के घरों तक पहुंचता है।

स्थानीय निवासी पोपट बताते हैं, "यहां के पटेल, ठाकुर, कहते हैं कि तुम नीच कौम के हो, इसलिए तुम अपने श्मशान में शरीर जलाओ।"

11 साल के मयूर ने बताया, "मंदिर की प्रतिष्ठा के वक्त वो प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं, हमें कागज़ पर खाना दिया जाता है। वो हमें दुतकारते हैं। इसलिए हम उधर नहीं जाते। जब हम बैठते हैं तो हमें उठा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। मेरे दिमाग में आता है कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। वो हमें ठेड़े (गुजराती में नीची जाति) कहकर चिढ़ाते हैं।"

गुजरात में हर वर्ष दलित उत्पीड़न के हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। इनमें मौखिक क्रूरता से लेकर बलात्कार तक के मामले शामिल हैं। 2014 में 100 से ज़्यादा गांवों में दलितों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी थी। आज ऐसे 14 गांव हैं।

अहमदाबाद के करीब 150 किलोमीटर दूर नंदाली गांव के एक खेत में मैं मजदूर बाबूभाई सेलमा से मिला। क़रीब एक हज़ार लोगों वाले इस गांव में केवल 20 दलित रहते हैं।

सेलमा के मुताबिक़ उन्हें स्थानीय राजपूत जुझार सिंह ने किसी बात पर कथित रूप से एक थप्पड़ मारा। जब वो मामला पुलिस के पास ले गए तो गांव में दलितों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया। रात 10 बजे गांव के बाहर स्थित उनके झोपड़े के बाहर सभी दलित इकट्ठे हुए। उनके साथ थे गुजरात पुलिस के विपुल चौधरी।

गांव में स्थित नंदी माता के मंदिर में दलित प्रवेश नहीं कर सकते। माचिस खरीदने के लिए भी दलितों को तीन किलोमीटर दूर खैरालू गांव जाना पड़ता है। राजपूतों की ज़मीन पर वो काम नहीं कर सकते इसलिए भूखों मरने की नौबत आ गई है।

जुझार सिंह मामले को फ़र्जी बताते हैं। लेकिन बेहिचक कहते हैं, "हम दलित के घर नहीं खाते, सारा गुजरात नहीं खाता। केजरीवाल खाता है। राहुल गांधी खाता है। हम नहीं।"

राम मंदिर आंदोलन में साथ, राम मंदिर में नहीं

गुजरात में वर्ण व्यवस्था और जाति बेहद महत्वपूर्ण है। राम मंदिर बनाने बहुत से दलित और आदिवासी भी अयोध्या गए थे। लेकिन जब वही दलित वापस अपने गांव आए तो उन्हें राम मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। शहरों में जाति-आधारित इमारतें हैं लेकिन गांवों में स्थिति बदतर है। उच्च जाति वाला अपने से नीची जाति के लोगों को नीची निगाह से देखता है।

एक वक्त था जब लोग पूछते थे, तुम्हारा दूध क्या है। दलित संख्या में कम हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है। आर्थिक कारणों और भेदभाव से दलित बच्चे बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाते। इस कारण वो आरक्षण के फ़ायदे से भी महरूम हैं। छूत-अछूत की समस्या सौराष्ट्र में सबसे विकट है।

समाजशास्त्री गौरांग जानी बताते हैं कि सौराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में सामंती सोच वाले राजाओं का राज था। राजा तो चले गए लेकिन सोच जीवित रही।

वो कहते हैं, "गुजरात में कोई नॉलेज ट्रेडिशन नहीं है। गांधीवादी सोच को किनारे रख दिया गया है। यहां कोई वाम आंदोलन नहीं हुआ। इस खालीपन में हिंदुत्ववादियों को जगह मिली। हिंदू एकता के नाम पर राजनीतिक दल हिंदुओं को साथ तो ले आए लेकिन दलितों की जिन्दगी बदलने की कोशिश नहीं की गई। पहले साथ रहना एक पाठशाला जैसा था। अब जाति आधारित आवासीय इमारतों के कारण पुराना बंधन टूट गया है।"

भूमंडलीकरण के दौर में जब सभी वर्ग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो दलित युवा ख़ुद की हालत देखते हैं और पूछ रहे हैं, आखिर विकास के दौर में उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है। अगर पटेल सरकार पर हावी हो सकते हैं तो दलित क्यों नहीं। आरक्षण विरोध प्रदर्शन और कई दंगे देख चुके गुजरात में दलित के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों की मानसिकता बदलने की है।

विनीत खरे की रिपोर्ट

खबर (दार) झरोखा

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगाने में मोदी सरकार का हाथ?

भाजपा के सबसे गाल बजाऊ प्रवक्ता कहे जाने वाले संबित पात्रा जब कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी से आज तक पर अंजना ओम कश्यप की उपस्थिति में चल रही डिबेट में विजय माल्या को जब माल्या जी कहते हैं तभी साफ हो जाता कि असल में मोदी के लोगों में लुटेरों को लेकर कितना प्रेम और आदर का भाव है।

गिरीश मालवीय

यह साबित हो गया है कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ओर नीरव मोदी को भारत से भगवाने में मोदी सरकार बराबर की भागीदार है। एंटीगुआ के कानून मंत्री स्टीडॉय बेंजमिन ने दावा किया है कि 2017 में जब मेहुल चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता के लिए आवेदन किया था तब भारतीय अधिकारियों ने कोई आपत्ति या रेड सिग्नल नहीं दिया था।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में मंत्री ने कहा, 'न तो किसी अधिकारी और न ही भारत की किसी भी संस्था ने मेहुल चोकसी पर ऐतराज जताया था।'

एंटीगुआ प्रशासन ने जानकारी दी है कि मेहुल चोकसी ने कैरेबियाई द्वीपीय देश की नागरिकता के लिए मई 2017 में आवेदन किया था। यह भी बताया गया है कि एंटीगा अधिकारियों को बाकायदा भारतीय विदेश मंत्रालय के स्थानीय पासपोर्ट ऑफिस से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था, जबकि उस वक्त भी गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी पर गम्भीर आर्थिक आरोप लगाए जा चुके थे।

2013 में ही सेबी ने मेहुल चौकसी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया था। उन पर आरोप थे कि गीतांजलि में ट्रेड करने के लिए चोकसी 25 शैल कंपनियों को फाइनेंस करते थे, उन पर 2014 में ही गीतांजलि के जनरल मेनेजेर ने भी गंभीर आरोप लगाये थे।

आयकर विभाग ने जनवरी 2017 में ही नीरव मोदी के घर समेत 50 दफ्तरों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक, छापेमारी में कैश, ज्वैलरी और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे, जो कथित तौर पर कर चोरी से जुड़े थे। सूत्रों ने बताया आयकर विभाग ने मोदी के मुंबई स्थित ऑफिस और घर, दिल्ली स्थित घर और जयपुर व सूरत स्थित यूनिट पर रेड मारी थी।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों में से एक गीतांजलि ग्रुप के दफ्तरों पर भी रेड मारी थी। दोनों कम्पनियों पर एक साथ रेड मारने से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों कम्पनियों के मिले—जुले घोटालों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थी।

यानी मामला उसी वक्त खुल चुका था, सारे कागजात इनकम टैक्स वालो की नजर मे आ चुके थे। नीरव मोदी की 150 से अधिक फर्जी कम्पनियां थीं। 2017 में ही इस सारे मामले की अंदरूनी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी, जिसमें नीरव मोदी की तरफ से अपनाए जाने वाले कामकाज के 10 तरीके की जानकारी दी गई है, जो मोदी व उनकी फर्म करवंचना के लिए करती थी7 तो उस वक्त किसके दबाव में यह रिपोर्ट दबाई गयी?

मार्च 2017 में गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर इस बात को लेकर चेता चुके थे कि गीतांजलि जेम्स ने एलआईसी के कर्ज भुगतान में डिफॉल्ट किया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी भरी सभा में मेहुल भाई जैसे संबोधन दे रहे हों तो पुलिस और कस्टम विभाग की क्या मजाल जो मेहुल भाई को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट न दे। इसके पहले 2016 में भी गीतांजलि जेम्स पर अनेक आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं।

इन खबरों से यह साफ जाहिर है कि कुल मिलाकर मोदी सरकार इस पीएनबी घोटाले के आरोपियों को हर तरह से बचाने को तत्पर नजर आ रही है।

मास्टर स्ट्रोक अब बिना बाधा के आएगा मास्टर (पुण्य प्रसून वाजपेयी) नहीं दिखेगा

एबीपीन्यूज़ में पिछले 24 घंटों में जो कुछ हो गया, वह भयानक है। और उससे भी भयानक है वह चुप्पी जो फ़ेसबुक और ट्विटर पर छायी हुई है। भयानक है वह चुप्पी जो मीडिया संगठनों में छायी हुई है।

मीडिया की नाक में नकेल डाले जाने का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों से नियोजित रूप से चलता आ रहा है, यह उसका एक मदान्ध उद्-घोष है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग तो दिल्ली में सत्ता-परिवर्तन होते ही अपने उस 'हिडेन एजेंडा' पर उतर आया था, जिसे वह बरसों से भीतर दबाये रखे थे। यह ठीक वैसे ही हुआ, जैसे कि 2014 के सत्तारोहण के तुरन्त बाद गोडसे, 'घर-वापसी', 'लव जिहाद', 'गो-रक्षा' और ऐसे ही तमाम उद्देश्यों वाले गिरोह अपने-अपने दड़बों से खुल कर निकल आये थे और जिन्होंने देश में ऐसा ज़हरीला प्रदूषण फैला दिया है, जो दुनिया के किसी भी प्रदूषण से, चेरनोबिल जैसे प्रदूषण से भी भयानक है। घृणा और फ़ेक न्यूज़ की जो पत्रकारिता मीडिया के इस वर्ग ने की, वैसा कुछ मैंने अपने पत्रकार जीवन के 46 सालों में कभी नहीं देखा। 1990-92 के बीच भी नहीं, जब रामजन्मभूमि आन्दोलन अपने चरम पर था।

मीडिया का दूसरा बहुत बड़ा वर्ग सुभीते से गोदी में सरक गया और चारण

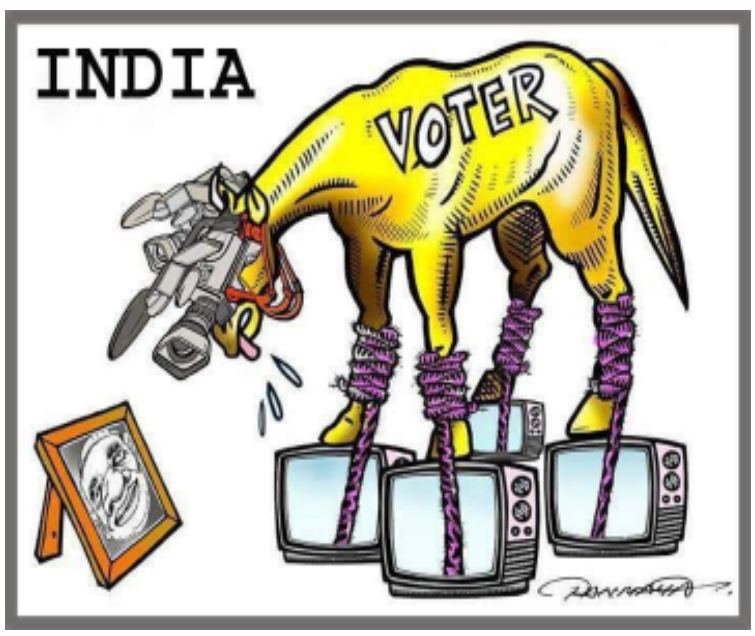

बन गया। जैसा कि उसने 1975 में इमर्जेंसी के बाद किया था। इतना ही नहीं, इस बार तो वह इस हद तक गटर में जा गिरा कि पैसे कमाने के लिए वह किसी भी तरह के साम्प्रदायिक अभियान में शामिल होने को तैयार दिखा। कोबरापोस्ट के स्टिंग ने इस गन्दी सच्चाई को उघाड़ कर रख दिया। लेकिन यह भयानक चुप्पी तब भी छायी रही। सोशल मीडिया में भी, पत्रकारों और पत्रकार संगठनों में भी और आम जनता में भी।

इसीलिए हैरानी नहीं होती यह देख कर कि एक मामूली-सी ख़बर को लेकर एबीपी न्यूज़ के सम्पादक मिलिंद खंडेडकर से इस्तीफ़ा ले लिया जाय और अभिसार शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाय। अभी ख़बर मिली कि पुन्य प्रसून वाजपेयी भी हटा दिये गये। उनके शो 'मास्टरस्ट्रोक' को पिछले कुछ दिनों से रहस्यमय ढंग से बाधित किया जा रहा था। इन सब घटनाओं पर कुछेक गिने-चुने पत्रकारों को छोड़ कर ज़्यादातर ने अपने मुँह सी रखे हैं। ऐसा डरा हुआ मीडिया मैं इमर्जेंसी के बाद पहली बार देख रहा हूँ। एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन मौन हैं। और इस सबसे भी भयानक यह कि देश इस सब पर चुप है।

हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अपनी व्यक्तिगत वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इन सब पर मन ही मन ख़ुश हो रहे हों। लेकिन क्या आज जो हो रहा है, वह भविष्य की सरकारों को इससे भी आगे बढ़ कर मीडिया को पालतू बनाने का रास्ता नहीं तैयार करेगा? अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी धारणाओं और अपने पूर्वग्रहों के मोतियाबिन्द से बाहर निकल कर देखिए कि आप भविष्य में किस तरह के लोकतंत्र की ज़मीन तैयार कर रहे हैं?